

दशम्

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग - 1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 1994 ई०

बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 1994 ई०

वृहस्पतिवार, दिनांक 14 जुलाई, 1994 ई०



सत्यमेव जयते

श्री अजीत सरकार: सभापति महोदय, अभी सरकार ने कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विश्वविद्यालय का भवन गिरवी है। मेरा कहना है कि इस क्वेश्चन को स्थगित करके सरकार को कहिये कि सरकार पता लगाकर अगले डेट में बतावे कि भवन गिरवी मे है या नहीं?

सभापति (श्री अनूप लाल यादव): माननीय सदस्य अजीत साहब , यह स्थगित प्रश्न है। जिन बिन्दुओं पर स्थगित किया गया था उन बिन्दुओं का जिक्र मंत्री ने कर दिया है।

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, आपने ठीक रूलिंग दे दिया कि जिस बिन्दु पर स्थगित हुआ था उसको माननीय मंत्री ने खुलासा कर दिया है। माननीया सदस्या ने जो पूछा , उस पर आपका आब्जर्वेशन हो गया कि आप स्पेसिफिक दे दें तो वे जांच करवा देंगे। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति (श्री अनूपलाल यादव): आप भी पुराने सदस्य हैं। मैंने मंत्री को कह दिया कि आप फिर से देख लीजिए, आपके नौलेज में नहीं है, जानकारी में नहीं है तो सरकार जानकारी लेकर माननीया सदस्या को पत्र लिख देंगी। फिर स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण

‘क’-२२. श्री राजीव प्रताप सिंह: दिनांक ५ जून, 1994 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित ‘बिहार में सिर्फ १७ प्रतिशत जंगल क्षेत्र शेष रहा’ शीर्षक को ध्यान में रखकर मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पर्यावरण संतुलन के लिये ३३ प्रतिशत वन होना जरूरी है, जब कि बिहार में मात्र १७ प्रतिशत भाग ही वन क्षेत्र है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार

पर्यावरण संतुलन हेतु सघन वृक्षारोपण योजना का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

सभापति: यह श्री प्रश्न स्थगित है और स्थगित जो हुआ है आप उसी का जवाब देंगे। आप जवाब दे दीजिए।

श्री सोनाधारी सिंहः सभापति महोदय, हमने मूल प्रश्न का उत्तर दे दिया था।

इनका सप्लीमेंटरी प्रश्न था कि 93-94 में 740 करोड़ रूपये का केन्द्र सरकार के पर्यावरण विभाग की योजना थी। इस वर्ष 1040 करोड़ की हो गई है। तो इससे बिहार को कितना फायदा होगा?

हुजूर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल केन्द्र सरकार के द्वारा 3 अरब से अधिक वृद्धि की गई है। राज्य सरकार को उससे करीब 15 करोड़ 97 लाख 20 हजार रूपये की वृद्धि हुई है। गत वर्ष से इस वर्ष में 11 करोड़ 59 लाख रूपये अधिक मिलने की संभावना है।

श्री राजीव प्रताप सिंहः सभापति महोदय, मैं एक विशेष व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ। जो माननीय सदस्य यह सुनेंगे, तो हतप्रभ रह जायेंगे। पिछली बार, जब मैंने प्रश्न किया था तो सदन ने इनके उत्तर से असंतुष्ट होकर इनसे समय लिया था। उसके पश्चात् मंत्री जी ने मुझे बुला कर कहा कि विभाग से इस प्रश्न का उत्तर तैयार करावेंगे। अगले दिन वन विभाग के तमाम पदाधिकारी मेरे निवास पर सुबह-सुबह पहुंच गये और कहा कि विभाग में इस विषय की फाइल नहीं है। विभाग में सब कुछ अस्तव्यस्त है। जो प्लानिंग डील करते हैं वे चले गये हैं। मंत्रीजी का आग्रह है कि उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आप कृपया इसे छोड़ दें।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव): इसमें क्या सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं वह पूछिये।

श्री राजीव प्रताप सिंहः सभापति महोदय, यह नया तरीका

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, यह कोई अनुचित बात नहीं है। विभाग में जब संचिका नहीं मिलती है तो हमलोग माननीय सदस्य को कहते हैं कि संचिका गुम हो गई है, इसलिए ये सप्लीमेंटरी पूछें, उसका जवाब होगा। डेरा पर क्या बात होती है, कैसे आपके यहां पहुंच जाते हैं इसका क्या जवाब होगा।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय सदस्य, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न पर पूरक पूछा गया था। पूरक प्रश्न एक ही है जो माननीय मंत्री जी को साफ करना था। जो प्रेसिडिंग में लिखा हुआ है उसको मैं साफ पढ़ देता हूं-'माननीय सदस्य का सवाल है कि पहले इस काम के लिए भारत सरकार ने 745 करोड़ रूपया रखा था और अब उसका लाभ बिहार सरकार को मिल रहा है या नहीं?' यही उत्तर देना है मंत्री जी सरकार को।

श्री सोनाधारी सिंह: 11 करोड़ 59 लाख रूपये का प्रस्ताव बना कर केन्द्र सरकार को भेजे हैं।

सभापति (श्री अनूपलाल यादव): माननीय मंत्री कहते हैं कि पैसा ही नहीं मिला है पैसा मिले, तब लाभ और नुकसान की बात होगी। अभी सरकार को पैसा मिला ही नहीं है।

श्री राजीव प्रताप सिंह: सभापति महोदय, हमने कहा था केन्द्र सरकार ने वास्तविक वित्तीय योजना में 40 परसेंट की वृद्धि की है, 400 करोड़ की वृद्धि की है। ये कहते हैं कि 11 करोड़ का प्रस्ताव बना कर भेजे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार को उसमें से कितना प्रतिशत प्राप्त होना था और कितना प्राप्त हुआ?

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय मंत्री, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और जिसका जवाब आपको देना है।

श्री सोनाधारी सिंह: हम सही जवाब दे रहे हैं इनके प्रश्न का।

श्री राजो सिंहः सभापति महोदय, इनसे यह भी पूछा जाये कि जंगल तो कम क्षेत्र में लगा ही है, इनका हाथी जंगल को काट-काट कर खा रहा है। उससे भी राज्य को नुकसान हो रहा है। ये जंगल काट-काट कर सभी हाथी को खिला रहे हैं।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सोनाधारी सिंहः इनका सप्लीमेंटरी प्रश्न था कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साढ़े तीन अरब रूपए की अधिक वृद्धि भारत सरकार के स्तर पर की गयी है। इस वृद्धि से बिहार सरकार को कितना फायदा होने वाला है? इस प्रश्न के आलोक में जवाब यह है कि 15 करोड़ 97 लाख 30 हजार रूपए अधिक मिलने की संभावना है लेकिन अभी मिला नहीं है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राजीव ग्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी सभापति महोदय ने कहा कि मंत्री जी का जवाब अस्पष्ट है।

श्री रघुनाथ झाः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित हुआ था इस प्लायांट पर कि वृद्धि जो भारत सरकार ने की है, उससे बिहार सरकार को कितना लाभ हो रहा है? इस पर मंत्री जी का जवाब मिला है कि 4 करोड़ सप्तर्थिंग पहली बार इस बार 11 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है लेकिन अभी पैसा भारत सरकार से नहीं मिला है। जब तक भारत सरकार से पैसा नहीं मिलता है तब तक यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजीव ग्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय ने भी इस पर नियमन दिया है। मैंने पूछा है कि 1040 करोड़ की वृद्धि की गयी है, 40 प्रतिशत की जो वृद्धि की गयी है भारत सरकार को बिहार सरकार द्वारा कितनी वृद्धि देनी है? ये जवाब उल्टा दे रहे हैं।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि योजना बनाकर भारत सरकार को भेजा गया है। 17 करोड़, 36 करोड़ का भेजा गया है। हम चाहते हैं कि ये उस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रख दें।

श्री सोनाधारी सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनका सप्लीमेंटरी है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार कितना अधिक मिलने की संभावना है। हम कहना चाहते हैं कि 1159 लाख अधिक मिलने की संभावना है। इनका प्रश्न ही अस्पष्ट है।

श्री राजीव प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा प्रश्न यह है कि कितने का प्रस्ताव भेजा गया। हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार को, बिहार सरकार को, कितना पैसा देने का प्रस्ताव है? आपने प्रस्ताव कितने का भेजा प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न है कि भारत सरकार में बिहार सरकार का कितना हिस्सा बनता है?

श्री सोनाधारी सिंह: बिहार सरकार का अंश कुछ नहीं है। टोटल 15 करोड़ 97 लाख 20 हजार रूपये का प्रस्ताव बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजा है। इसमें राज्य सरकार को कहां देना है?

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री शक्कील अहमद: अध्यक्ष महोदय, अभी जो आप मीटिंग करने गये थे उसमें क्या हुआ? सदन को यह जानने का अधिकार है। विरोधी दल के नेता, सभी दल के नेता गये थे। क्या निर्णय हुआ यह सदन को जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष: ठीक है। सदन को जानने का अधिकार है।

हम सदन को सूचना देना चाहते हैं कि श्री रामाश्रय सिंह, श्री स्वामीनाथ तिवारी, श्री वृजमोहन सिंह, श्री त्रिवेणी तिवारी, श्री स्टीफेन मराण्डी, श्री रवीन्द्र चरण यादव, श्री उदय नारायण चौधरी, श्री रघुनाथ गुप्ता और श्री राजेन्द्र सिंह बिस्मिल की ज्वायंट इंक्वायरी कमिटी बनाई गयी है। ये 5 दिनों के अन्दर अपना रिपोर्ट जांच कर

दे देगी। सरकार संबंधित पदाधिकारियों था डी०एस०पी०, एस०डी०ओ० को वहां से हटायेगी।

अब मैं अपने पत्रकार बंधुओं से अपील करना चाहूंगा। वे हैं।

जब पत्रकार वाशिंगटन की खबर को पढ़ना में सुनते हैं इसलिए घबराइए नहीं, वे हमारी वातों का सुन रहे होंगे। वे आ जायें और आकर बैठे। इस समिति के सभापति श्री रामाश्रय सिंह होंगे।

श्री लालमुनि चौबै: कुछ अल्पसूचित सवाल ऐसे हैं जो शोरगुल में पार कर गये। मैं अनुरोध करता हूँ कि उस प्रश्न को पुनर्जीवित किया जायें।

अध्यक्ष: हम एक ही प्रश्न पुट कर सकते हैं। सात-सात नहीं।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने ज्वायर्ट कमिटी बनायी है। उस हाउस के मेंबर भी इस कमिटी में सम्मिलित हों ऐसा आप कह दें।

अध्यक्ष: हाँ, विधान-परिषद से है:- माननीय सदस्य श्री रघुनाथ गुप्ता एवं श्री राजेन्द्र सिंह बिस्मिल।

श्री फुरकान अंसारी: अध्यक्ष महोदय, जामताड़ा भ्रमण के समय आपने कहा था हमने प्रश्न किया है। हुजूर हमारा प्रश्न पुट कर दीजिए या इसको पैंडिंग कर दीजिए।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षकों की पदस्थापना

क. 88. श्री कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह:

क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

- (1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत लखीसराय प्रखंड के बलिपुर एम०आर०एम०पी० उच्च विद्यालय जिले के पुराने विद्यालयों में से एक है;